

श्री मिथलेश कुमार : साहब, बस एक मिनट और दे दें। शहरों का विकास क्यों जरूरी है? सर, बस आधे मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। हम लोग नगर निगम में छोटे शहरों में रहते हैं, तो वहां के बच्चों को जब स्कूलिंग करनी होती है, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, चाहे मेडिकल की पढ़ाई हो, चाहे मैनेजमेंट की पढ़ाई हो, उसके लिए उनको बड़े शहरों की तरफ देखना पड़ता है। जब वे नौकरी प्राप्त करने जाते हैं, तो कहा जाता है कि छोटे शहर से पढ़कर आए हैं, तो इंजीनियर लोगों को वे लोग पीछे बैठा देते हैं। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि शहरों को बढ़ावा दें और शाहजहांपुर, जहां से मैं आता हूं, वह नगर निगम हो गया है, अगर हो सके, तो वहां के लिए नगर निगम की कुछ व्यवस्था कर दें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, if the House agrees, the remaining discussion on the working of the Ministry of Housing and Urban Affairs will be resumed at 1.00 p.m. tomorrow.

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, we had taken up permitted Special Mentions earlier in the day. All Members up to Sl.No. 31, except the hon. Member at Sl. No. 9 who was absent, had made their respective Special Mentions. I will now call the remaining Members starting with serial number 32. Shri Mithlesh Kumar.

SPECIAL MENTIONS - *Contd.*

Demand for Mailani-Farrukhabad new railway line project

श्री मिथलेश कुमार (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान मैलानी-फर्रुखाबाद नई रेल लाइन परियोजना के तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूँ। मैलानी-फर्रुखाबाद नई रेलवे लाइन बिछाने हेतु सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है, परंतु इस परियोजना पर अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है।

(उपसभापति महोदय पीठासीन हुए।)

लगभग 150 किलोमीटर लंबी इस रेल परियोजना के पूरा होने के बाद इस क्षेत्र में निवास करने वाले लाखों लोगों के लिए वरदान साबित होगा तथा इस पिछड़े क्षेत्र में व्यवसाय तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा रेलवे की आय में वृद्धि होगी।

यह नई रेल लाइन विकास के नए आयाम स्थापित करने के साथ-साथ सामरिक दृष्टिकोण से भी उपयोगी बन सकेगी। सैन्य छावनियों के कारण शाहजहांपुर और फतेहगढ़ जैसे

सुरक्षा की दृष्टि से सामरिक केंद्रों का जुड़ाव सीधे मथुरा, आगरा, ग्वालियर, झांसी तथा टनकपुर स्थित छावनियों से होने से संवेदनशील रहने वाली उत्तरी सीमा को मजबूती मिल सकेगी।

अतः मैं सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इस जनहित की परियोजना मैलानी-फर्रुखाबाद नई रेल लाइन पर इसी वर्तमान बजट में धन अवमुक्त करके यथाशीघ्र कार्य का शुभारंभ कराने की कृपा करें, जिससे इस परियोजना के पूरा होने के बाद क्षेत्र के विकास के साथ-साथ देश को सामरिक मजबूती मिलेगी।

श्री उपसभापति : माननीय श्री संजय राउत जी, present नहीं हैं। माननीय डा. राधा मोहन दास अग्रवाल जी, मौजूद नहीं हैं। माननीय श्री नीरज डांगी जी।

Demand for directions for mandatory display of the Preamble of Constitution of India in all the Government institutions

SHRI NEERAJ DANGI (Rajasthan): Sir, the Government of India has mandated the display of Mahatma Gandhi's portrait in all Government offices, public institutions and courts, as a mark of respect and to inspire citizens. All Government institutions have been directed to display Dr. Ambedkar's portrait also, recognizing his contributions to social justice, equality and the Constitution of India. This mandate is based on Supreme Court directives and various Government notifications and circulars from 2013 to 2019. Compulsory displaying these portraits serves as a reminder of their contributions to India's freedom, social justice and constitutional values.

In year 2019, the Supreme Court directed all educational institutions to display the Preamble of the Constitution of India in their premises. Displaying the Preamble acknowledges its significance as an integral part of the Constitution and India's governance framework. Like all schools and educational institutions, all Government institutions should also display the Preamble prominently, fostering a sense of national unity, values and constitutional responsibility. The display of Preamble of the Constitution of India in all Government institutions will: firstly, promote national integration, reflecting the country's commitment to sovereignty, socialism, secularism and democracy; secondly, embody the fundamental values and principles enshrined in the Constitution, serving as a reminder to public servants; thirdly, inspire and educate citizens about India's constitutional heritage and core values; fourthly, symbolize the national pride and identity, reflecting the country's history, philosophy and aspirations.

Therefore, Sir, I urge the Government of India to issue appropriate direction to all Government institutions for mandatory displaying the Preamble of the Constitution of India in their premises. Thank you.